माननीय न्यायमूर्ति ए. एस. बैंस के समक्ष
केहर सिंह, - याचिकाकर्ता।
बनाम
बाल किशन आदि, - उत्तरदाता।
1978 का आपराधिक विविध संख्या 1560-एम, 1 सितंबर, 1978।

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का 2) - धारा 145 (1) और 146 (1) - आपातकाल के आधार पर धारा 146 (1) के तहत संपत्ति की कुर्की - धारा 145 के तहत शुरू की गई कार्यवाही - क्या ऐसी कुर्की पर समाप्त होती है।

यह अभनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 145 (1) के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि आपातकाल के मामले में धारा 145 (1) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद संहिता की धारा 146 (1) के तहत कुर्की का आदेश दिया जा सकता है। धारा 146 में मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 145 के तहत शुरू की गई जांच को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी निषेध या प्रतिबंध पर विचार नहीं किया गया है। यदि विधायिका का इरादा कार्यवाही को जारी रखने की शक्ति को वापस लेने का था, तो विधायिका ने संहिता की धारा 146 के तहत कुर्की का आदेश दिए जाने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 145 के तहत आगे की कार्यवाही के लिए प्रतिबंध लगा दिया होता। धारा 145 के प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि विधायिका ने किसी भी तरह से मजिस्ट्रेट को कुर्की का आदेश दिए जाने के बाद आगे बढ़ने से नहीं रोका है। इसके बजाय, मजिस्ट्रेट को बाद में निर्दिष्ट तिथि और समय पर पार्टियों को बुलाने का अधिकार है और पार्टियों को अपने दावे रखने की भी आवश्यकता है और मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 145 के तहत उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को जारी रखने और अपने निष्कर्ष को समाप्त करने के लिए बाध्य है। धारा 146 के शुरुआती भाग में धारा 145 की उप-धारा (1) के तहत आदेश देने के बाद किसी भी समय मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 145 के तहत कार्यवाही जारी रखने के अधिकार क्षेत्र को किसी भी दर पर व्यक्त करने से मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार, संहिता की धारा 145 और 146 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, इस आशय का कोई निषेध, व्यक्त या निहित नहीं है कि धारा 145 (1) के तहत कार्यवाही तब समाप्त होनी चाहिए जब आपातकालीन स्थिति में कुर्की का आदेश दिया जाता है।

(पैरा 2)

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका में कहा गया है कि:-

1. मामले के रिकॉर्ड तलब किए जाएं;
2. रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद कार्यवाही और आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाए, यह घोषित करते हुए कि यह अधिकार क्षेत्र के बाहर है।
3. कोई भी अन्य आदेश जिसे यह माननीय न्यायालय उचित समझता है, पारित किया जाए, और आगे प्रार्थना करता है कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगाई जाए।

एस. एस. याचिकाकर्ता की ओर से राठौर, वकील।
एन. एस. अहलावत, एडवोकेट, एना आर. एन. अग्रवाल, एडवोकेट, प्रतिवादियों के लिए।

निर्णय
माननीय न्यायमूर्ति ए. एस. बैंस

1. यह याचिका कार्यकारी मजिस्ट्रेट (श्रीमती मंजू गुप्ता), सोनीपत के 24 नवंबर, 1977 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि प्रतिवादी कब्जे में रहने के हकदार थे और विवाद में भूमि की कुर्की का आदेश खाली कर दिया था। इस आदेश को 21 मार्च, 1978 को सोनीपत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (श्री राम सरन भाटिया) ने पलट दिया था।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिया गया एकमात्र तर्क यह है कि मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) के तहत आक्षेपित आदेश पारित नहीं कर सकता है क्योंकि उसने संहिता की धारा 146 (1) के तहत कुर्की का आदेश पारित किया था। जाहिर है, पक्षकार सिविल कोर्ट में भी गए हैं जिसने मामले को दूसरे पक्ष के पक्ष में फैसला दिया है, जो वर्तमान याचिका में प्रतिवादी हैं। कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि आक्षेपित आदेश के तहत यह निर्णय लिया गया है कि दूसरा पक्ष तब तक कब्जे में रहने का हकदार है जब तक कि कानून के अनुसार उसे बाहर नहीं निकाल दिया जाता और दूसरा, पक्ष उस धन का भी हकदार है जो रिसीवर द्वारा इस मामले के दौरान विवाद में भूमि की आय से एकत्र किया गया था और कुर्की आदेश को खाली कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने पटना के कुछ अधिकारियों पर भरोसा किया। राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसमें यह माना गया है कि संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही संहिता की धारा 146 के तहत आदेश पारित होते ही समाप्त हो जाती है। इन अधिकारियों के बारे में मोहम्मद मुस्लेहुद्दीन और एक अन्य बनाम मोहम्मद सलाहुद्दीन, 1976 सीआरएल जे 1150 (पाट) (1), फ्लैकिम सिंह और अन्य बनाम गिरवर सिंह और अन्य, 1976 सी.आर.एल.जे. 1915 (दिल्ली) (2) और मनसुख राम बनाम मनसुख राम मामले में रिपोर्ट किया गया है। राज्य और दूसरा, 1977 सीआरपीसी 563 (राज) (3)। विद्वान वकील का तर्क यह है कि एक बार आपातकाल के आधार पर संहिता की धारा 146 (1) के तहत कुर्की की जाती है, तो धारा 145 के तहत कार्यवाही समाप्त हो जाती है- वह संहिता की धारा 146 (1) में दिखाई देने वाले शब्दों पर विशेष जोर देता है "जब तक कि एक सक्षम अदालत ने उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति के संबंध में पार्टियों के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया है"। ऐसे मजिस्ट्रेट को विवाद की विषय वस्तु के संबंध में शांति भंग होने की संभावना न होने के कारण अपनी संतुष्टि पर कुर्की वापस लेने का अधिकार देने वाले प्रावधान। (पुरानी) संहिता के तहत, मजिस्ट्रेट को धारा 145 (4) के तहत जांच से पहले या जांच पूरी होने के बाद आपातकालीन स्थिति में संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार दिया गया था। वर्तमान संहिता के तहत आपात स्थिति में पहले प्रकार की कुर्की को 'मामले में अपना फैसला लंबित रहने' वाले अर्हक शब्दों के साथ समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, कार्यकारी मजिस्ट्रेट को (पुरानी) संहिता के तहत धारा 145 (4) के तहत जांच शुरू होने से पहले या उसके निष्कर्ष के बाद आपातकालीन स्थिति में भूमि को कुर्क करने का अधिकार दिया गया था। वर्तमान संहिता के तहत, मजिस्ट्रेट को विवाद की विषय वस्तु को संलग्न करने और संहिता की धारा 146 (1) के तहत एक रिसीवर नियुक्त करने का अधिकार देने के लिए एक अलग प्रावधान बनाया गया है, जो निम्नलिखित शर्तों में है:-

> "यदि मजिस्ट्रेट किसी भी समय धारा 145 की उप-धारा (1) के तहत आदेश देने के बाद मामले को आपातकाल में से एक मानता है, या यदि वह तय करता है कि कोई भी पक्ष उस कब्जे में नहीं था जैसा कि धारा 145 में संदर्भित है, या यदि वह खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि उनमें से कौन विवाद के विषय के ऐसे कब्जे में था, वह विवाद के विषय को तब तक संलग्न कर सकता है जब तक कि एक सक्षम न्यायालय ने उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति के संबंध में पार्टियों के अधिकारों को निर्धारित नहीं किया है: बशर्ते कि ऐसा मजिस्ट्रेट किसी भी समय कुर्की वापस ले सकता है यदि वह संतुष्ट है कि विवाद के विषय के संबंध में शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है।"
>
> उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि धारा 146 (1) के तहत कुर्की की जा सकती है, सबसे पहले, आपातकालीन स्थिति में; दूसरा, यदि मजिस्ट्रेट यह निर्णय लेता

है कि कोई भी पक्ष ऐसे कब्जे में नहीं था जैसा कि धारा 145 में संदर्भित किया गया है, और तीसरा, यदि वह खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि विवाद में भूमि के कब्जे में कौन सा पक्ष था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कुर्की आदेश पारित करने के लिए शर्तें यह हैं कि आपातकाल होना चाहिए और मजिस्ट्रेट का सकारात्मक निर्णय है कि कोई भी पक्ष विवाद की विषय वस्तु के वास्तविक भौतिक कब्जे में नहीं था और वह खुद को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि कौन सा पक्ष वास्तविक भौतिक कब्जे में था। कुर्की का आदेश तब पारित किया गया जब मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 145 (1) के तहत आदेश पारित किया और इसे आपातकाल का मामला माना, हालांकि आक्षेपित आदेश में उसने यह भी कहा है कि विवाद में भूमि पर किसी भी पक्ष का कब्जा नहीं है, लेकिन कुर्की आदेश संहिता की धारा 145 (1) के तहत आदेश पारित करने के बाद ही पारित किया गया था। संहिता की धारा 145 (1) निम्नलिखित शब्दों में है:-

> "जब भी कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य जानकारी पर संतुष्ट होता है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भूमि या पानी या उसकी सीमाओं के संबंध में शांति भंग होने की संभावना वाला विवाद मौजूद है, तो वह लिखित रूप में एक आदेश देगा, जिसमें उसके संतुष्ट होने का आधार बताया जाएगा, और ऐसे विवाद में संबंधित पक्षों को एक निर्दिष्ट तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा अपने न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, और विवाद के विषय के वास्तविक कब्जे के तथ्य के संबंध में अपने संबंधित दावों के लिखित बयान देने होते हैं।"

इस प्रावधान को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि आदेश पारित करने से पहले, मजिस्ट्रेट को खुद को संतुष्ट करना होगा कि पक्षों के बीच शांति भंग होने की संभावना है और आदेश में अपनी संतुष्टि के आधार को दर्ज करना होगा, ऐसे विवाद में संबंधित पक्षों को एक विशिष्ट तारीख और समय पर अदालत में उपस्थित होने और विषय के वास्तविक तथ्यों के संबंध में लिखित बयान देने की आवश्यकता होगी। विवाद की स्थिति। इसलिए, प्रावधान से यह स्पष्ट है कि आपातकाल के मामले में धारा 145 (1) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद संहिता की धारा 146 (1) के तहत कुर्की का आदेश दिया जा सकता है। धारा 146 में मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 145 के तहत शुरू की गई जांच को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी निषेध या प्रतिबंध पर विचार नहीं किया गया है। मेरी सुविचारित राय में, यदि विधायिका का इरादा कार्यवाही को जारी रखने की शक्ति को वापस लेने का होता, तो विधायिका ने संहिता की धारा 146 के तहत कुर्की का आदेश दिए जाने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 145 के तहत आगे की कार्यवाही के लिए प्रतिबंध लगा दिया होता।

इस प्रावधान को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि आदेश पारित करने से पहले, मजिस्ट्रेट को खुद को संतुष्ट करना होगा कि पक्षों के बीच शांति भंग होने की संभावना है और आदेश में अपनी संतुष्टि के आधार को दर्ज करना होगा, ऐसे विवाद में संबंधित पक्षों को एक विशिष्ट तारीख और समय पर अदालत में उपस्थित होने और विषय के वास्तविक तथ्यों के संबंध में लिखित बयान देने की आवश्यकता होगी। विवाद की स्थिति। इसलिए, प्रावधान से यह स्पष्ट है कि आपातकाल के मामले में धारा 145 (1) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद संहिता की धारा 146 (1) के तहत कुर्की का आदेश दिया जा सकता है। धारा 146 में मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 145 के तहत शुरू की गई जांच को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी निषेध या प्रतिबंध पर विचार नहीं किया गया है। मेरी सुविचारित राय में, यदि विधायिका का इरादा कार्यवाही को जारी रखने की शक्ति को वापस लेने का होता, तो विधायिका ने संहिता की धारा 146 के तहत कुर्की का आदेश

दिए जाने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 145 के तहत आगे की कार्यवाही के लिए प्रतिबंध लगा दिया होता:-

> "आपातकाल के आधार पर संहिता की धारा 146 (1) के तहत कुर्की का आदेश दिए जाने के बाद संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही समाप्त नहीं होती है। 1976 क्रि.एल.जे. 1150 (पैट): 1976 क्रिल जे. 1915 (दिल्ली): 1977 क्रि.एल.जे. 563 (राज), 1977 से असहमति, 1977 असम एलआर 58 ने फैसला सुनाया धारा 146 (1) में अभिव्यक्तियों का उपयोग कुर्की के आदेश की शुरुआत का संकेत है और इससे अधिक कुछ नहीं। धारा 146 के शुरुआती भाग में अभिव्यक्तियों का उपयोग। किसी भी दर पर, कार्यवाही जारी रखने के लिए मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र को न छीनना स्पष्ट और स्पष्ट है। दूसरी ओर वे केवल कुर्की के आदेश के शुरू होने की तारीख को इंगित करते हैं। इसलिए, जब किसी न्यायालय को कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, तो यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक और उचित है कि कानून उसे कार्यवाही समाप्त करने का अधिकार देता है।"

मैं गौहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा प्रतिपादित कानून के प्रस्ताव से पूर्णत सहमत हूं। इस प्राधिकरण में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए अधिकारियों पर ध्यान दिया गया है।

3. ऊपर दर्ज कारणों के लिए, मैं मानता हूं कि संहिता की धारा 146 (1) के तहत कुर्की का आदेश पारित होने के बाद संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही जारी रखने के लिए मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं किया जाता है। धारा 145 में होने वाले "किसी भी समय" शब्द इंगित करते हैं कि कुर्की का आदेश या तो धारा 146 (1) के तहत पारित आदेश के बाद या संहिता की धारा 145 (4) के तहत कार्यवाही के समापन के बाद पारित किया जा सकता है। कुर्की आदेश पारित होने के बाद कब्जे के संबंध में कोई आदेश पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं जो दृष्टिकोण अपना रहा हूं वह हमारे अपने उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय से भी समर्थित है, जिसे सतगुरु जगजीत सिंह आदि बनाम जीत कौर आदि (5) के रूप में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें इसे निम्नानुसार माना जाता है:-
"... नई संहिता की धारा 146 (1) के तहत कुर्की से धारा 145 के तहत कार्यवाही समाप्त नहीं होती है और मजिस्ट्रेट जिसने संहिता की धारा 145 (1) के तहत प्रारंभिक आदेश पारित किया है, उसे मामले के साथ आगे बढ़ने का अधिकार है और पार्टियों के बयान और उसके सामने पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रावधानों के प्रकाश में कब्जे का निर्धारण करना होगा। संहिता की धारा 145(4)।"

4. ऊपर दर्ज कारणों के लिए, यह याचिका विफल और खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हिमांशु जांगड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी